

सहायक सचिव
(S.D.O.) बालोत्तरा

30.7.2025 दोनो पक्षो के संधिपत्रा उपर
वकील विद्यापी की कर ले जो. नूधर

विजयजित की कर
से वेगपारी के
कोई कउना नही
[Signature]
[Signature]

- मगल - -

101/2020

ख
म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

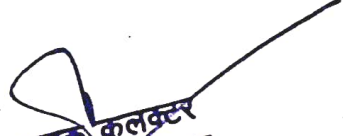
नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

प्लीड किया गया है, इसी सुरत में उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा शेष विप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही हो रखी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है तथा प्रकरण वादी साक्ष्य में विचाराधीन चला रहा है। इस कारण विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सुरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 29.7.2020 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा